

## Rapid Fire करेंट अफेयर्स (23 August)

- भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की पाँचवें दौर की बैठक 21-22 अगस्त को काठमांडू में आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान भारत और नेपाल के बीच खाद्य सुरक्षा और मानकों पर समझौता ज़ापान पर हस्ताक्षर हुए। इस पर नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण वभिग (DFTQC) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हस्ताक्षर किया। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके नेपाली समकक्ष प्रदीप कुमार ग्रावली ने संबंधित प्रत्याक्षरियों के साथ इस बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने वशिष्ठ रूप से कनेक्टिविटी और आरथिक साझेदारी, व्यापार और पारगमन, बजिली और जल संसाधन क्षेत्रों, संस्कृति और शक्तिका क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान वर्ष 1950 की शांति और मत्रिता संधि की समीक्षा हुई और नेपाल-भारत संबंध पर एक रपिएट का आदान-प्रदान किया गया। भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की चौथी बैठक नई दिल्ली में 27 अक्टूबर 2016 को आयोजित की गई थी।
- भारतीय रेलवे ने पर्यावरण को प्लास्टिक के खतरे से बचाने के लिये पहल करते हुए रेलवे की सभी यूनिटों को 2 अक्टूबर से 50 माइक्रॉरैन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रत्याक्षर लगाने का निर्देश दिया है। इसके तहत एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री पर प्रत्याक्षर लगाया जाएगा तथा सभी रेलवे वेंडरों को प्लास्टिक के बैग का उपयोग करने से बचना होगा। रेलवे करमचारियों को प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कम करने को कहा गया है। IRCTC वसितारति उत्पादक जमिमेदारी के हसिसे के रूप में प्लास्टिक की पेयजल वाली बोतलों को लौटाने की व्यवस्था लागू करेगा। शीघ्र ही प्लास्टिक की बोतलों को पूरी तरह तोड़ देने वाली मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। मौजूदा समय में देश के 170 रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने की व्यवस्था है। इसके अलावा रेलवे की सुविधाओं का उपयोग करने वालों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये सूचना, शक्तिका और संचार संबंधी उपायों की मदद ली जाएगी।
- लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन परसिर में प्लास्टिक की बोतलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रत्याक्षर लगा दिया है। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर जारी निर्देश में संसद भवन में काम करने वाले अधिकारियों और करमचारियों को प्लास्टिक के सामान के बजाय पर्यावरण अनुकूल थैलों या सामान का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रत्याक्षर लगा दिया है। देशभर में ऐसे करीब दो हजार स्कूल हैं। इसके साथ ही देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों से इसके इस्तेमाल पर रोकथाम के जरूरी कदम उठाने को कहा है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को महाराष्ट्र में अमरावती ज़िले के फूपगांव में हाल ही में किये गए उत्खनन में विद्रभ क्षेत्र में लौहकालीन बस्ती होने के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल पर खुदाई दिसंबर, 2018 और मार्च, 2019 के बीच की गई थी। ASI की टीम ने फूपगांव के चंद्र बाजार से पूर्णा बेसनि के दरयापुर के बीच के क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण किया। यह स्थल तापी की परमुख सहायक नदी पूर्णा नदी के वशिल घुमावदार मार्ग में स्थिति है, जो बारहमासी नदी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ऊपरी धारा में बांध का नरिमाण हो जाने के कारण पूरी तरह सूख चुकी है। यह स्थल नदी के तल से लगभग 20 मीटर की दूरी पर स्थिति है और पुराने ज़माने में पानी की तेज़ धार के कारण इसके एक-तहिंई हसिसे में बार-बार भूमिकाटाव होता था। कुल 9 खाइयों में खुदाई की गई, जिनसे मकान और चूल्हा, पोस्ट-होल और कलाकृतियों जैसे अवशेष मिले। खुदाई के दौरान, 4 पूर्ण गोलाकार संरचनाएं मिलीं। उत्खनन से एट-कारेलियन, जैस्पर, क्वार्टज और एट जैसे मोतियों की भी बड़ी मात्रा का पता चला। सभी खाइयों से लोहे, तांबे की वस्तुएं भी एकत्रित की गई हैं। बरतनों के टूटे हुए टुकड़ों पर बड़ी मात्रा में भत्तितचित्रियों के निशान मिले हैं। कालक्रमानुसार इस स्थान को 7 इसा पूर्व और 4 इसा पूरव के बीच रखा जा रहा है।
- 21 अगस्त को दुनियाभर में विश्व वरषित नागरकि दविस का आयोजन किया गया। विश्व वरषित नागरकि दविस की पहली बार घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर, 1990 को की थी। वैसे विश्व वरषित नागरकि दविस का इतिहास वर्ष 1988 से शुरू होता है। इसे आधिकारिक तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने शुरू किया था। उन्होंने 19 अगस्त, 1988 को इस पर हस्ताक्षर किया थे, जिसे 21 अगस्त को वरषित नागरकि दविस के रूप सामने लाया गया था। रोनाल्ड रीगन पहले राष्ट्रीय वरषित नागरकि दविस को पेश करने वाले पहले व्यक्तिथे। विदित हो कि भारत सरकार अपने वरषित नागरकियों को कई सुविधाएँ देती है। 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरकि सभी सरकारी सुविधाओं के हकदार हैं। इन्हें रेलवे के करिए में 40 प्रतशित छूट दी जाती है। सरकारी बसों में कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। एयरलाइन्स में 50 प्रतशित तक की छूट देने की व्यवस्था रखी गई है। बैंकों तथा अस्पतालों में भी इन्हें कई सुविधाएँ प्राप्त हैं। इस दविस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की स्थितिके बारे में जागरूकता फैलाना है और उन्हें शिटाचार की प्रक्रिया के माध्यम से समर्थन देना है। इस दिन को वृद्ध लोगों के कल्याण के लिये भी मनाया जाता है ताकि उनकी क्षमता, ज़ान उपलब्धियों और योग्यता की सराहना की जा सके। इस वर्ष इस दविस की थीम **The Journey to Age Equality** रखी गई है।